मंत्री सीतारमण की मिस्र के मंत्री से चर्चा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, फिनटेक और युवाओं के लिए सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

जयपुर, 13 अगस्त. केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने को ब्रिक्स समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान मिस्र के वित्त मंत्री अहमद कूचौक से मुलाकात की.

दो दिवसीय बैठक के पहले दिन हुई इस द्विपक्षीय बातचीत में भारत और मिस्र के बीच वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. सीतारमण ने ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता को मिस्र की ओर से दिए गए मजबूत समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. बैठक में दोनों नेताओं ने वित्तीय क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्व पर विचार साझा किए. विशेष रूप से जोखिम का आकलन करने और धोखाधड़ी का पता लगाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर चर्चा हुई. इसके साथ ही स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का निपटान, वित्तीय प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में संरचित सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई. दोनों पक्षों ने माना कि तकनीक और नवाचार के प्रभावी इस्तेमाल से वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, तेज और सक्षम बनाया जा सकता है. सीतारमण ने कहा कि भारत और मिस्र के बीच आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को और आगे बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं. बातचीत में ब्रिक्स के नव विकास बैंक की भूमिका को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया. परियोजनाओं के विकास के साथ निजी पूंजी जुटाने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और जोखिम कम करने से जुड़े तंत्र में दोनों देशों के अनुभवों को साझा करने की जरूरत पर सहमति बनी.

> माना गया कि छोटे और मझोले उद्यम रोजगार, नवाचार और स्थानीय आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. बैठक में हुई चर्चा से यह संकेत मिला कि भारत और मिस्र पारंपरिक आर्थिक संबंधों से आगे बढ़कर तकनीक, नवाचार, वित्तीय सहयोग, निजी निवेश और युवा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई दिशा देना चाहते हैं. ब्रिक्स मंच पर दोनों देशों के बीच बढ़ता समन्वय वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

99 रुपये से गिग वर्कर्स का पेंशन खाता शुरू

नई दिल्ली, 13 अगस्त देश के लाखों गिग वर्कर्स के लिए पेंशन सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और अर्बन कंपनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारी अब केवल 99 रुपये के शुरुआती योगदान के साथ नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़कर अपने रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार कर सकेंगे. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एनपीएस मॉडल की जानकारी साझा की है. पीएफआरडीए के अनुसार, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए तैयार किए गए इस मॉडल का उद्देश्य उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, जिनकी आय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है. अब तक बड़ी संख्या में ऐसे कामगार नियमित पेंशन योजनाओं से दूर थे.

मेक इन इंडिया वैश्विक बनाएं : गोयल

भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर

निर्यात बढ़ाने डिजिटल तकनीक और विनिर्माण अपनाने की अपील

नई दिल्ली, 13 अगस्त. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग जगत और नागरिकों से अपील की है कि वे देश में बने उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए उचित व्यापार प्रथाओं को अपनाएं.

उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' अभियान को केवल देश तक सीमित रखने के बजाय स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक ले जाने की जरूरत है. इसके लिए गुणवत्ता, बेहतर डिजाइन, डिजिटल तकनीक और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली को अपनाना जरूरी होगा.

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की वैश्विक आर्थिक भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने बताया कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योगों और व्यवसायों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अवसर खुले हैं. इन समझौतों से भारतीय उत्पादों और सेवाओं को कई देशों में बेहतर पहुंच मिल रही है. उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका में छोटे और मध्यम उद्यमों, किसानों, मछुआरों, श्रमिकों, उद्यमियों और सेवा क्षेत्र के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है. इन सभी वर्गों की भागीदारी से भारत अपनी आर्थिक क्षमता को और मजबूत कर सकता है. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वर्तमान में करीब चार ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है.

>
>
> गोयल ने भारत के निर्यात प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्ष वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा. उन्होंने बताया कि निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है और चालू वर्ष में एक ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि अप्रैल से जुलाई के शुरुआती चार महीनों में निर्यात में करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

यूपीआई से 6जी तक डिजिटल बदलाव

6जी, एआई और सेमीकंडक्टर से तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

गांवों से वैश्विक बाजार तक बढ़ी डिजिटल कनेक्टिविटी

नई दिल्ली, 13 अगस्त भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और नागरिक सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) ने सरकारी सेवाओं को कागजी प्रक्रियाओं और भौतिक कार्यालयों से निकालकर एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है.

पिछले एक दशक में डिजिटल तकनीक ने नागरिकों, सरकार और संस्थानों के बीच संपर्क को आसान, तेज और पारदर्शी बनाया है. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब विकास के प्रमुख आधारों में शामिल हो चुकी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार ने न केवल सेवा वितरण को मजबूत किया है, बल्कि व्यापार, रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी पैदा किए हैं. यूपीआई, आधार, डिजीलॉकर, भारतनेट, ओएनडीसी और सरकारी ई-मार्केटप्लेस जैसे डिजिटल माध्यमों ने आम नागरिकों और कारोबारियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है.

मेक इन इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत हुई है.

> शिक्षा और कौशल विकास में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे माध्यमों ने छात्रों और शिक्षकों तक डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाई है. साथ ही फ्यूचरस्किल्स और इंडिया-एआई मिशन जैसी पहलें भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने पर केंद्रित हैंकुल मिलाकर भारत का डिजिटल इकोसिस्टम केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सुशासन, आर्थिक विकास और नागरिक सशक्तिकरण का नया आधार बन रहा है.

कम प्रीमियम में 10 साल सुरक्षा कवर

भोपाल, 13 अगस्त आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईप्रोटेक्ट स्मार्ट अब 10 साल के लाइफ कवर विकल्प के साथ उपलब्ध है. यह प्लान उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जिनके पास कुछ निश्चित वित्तीय जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे आवास ऋण, बच्चों की पढ़ाई के लक्ष्य और व्यावसायिक ऋण. इससे ग्राहक अपने जीवन के उस दौर में कम प्रीमियम पर अधिक लाइफ कवर चुन सकते हैं, जब उनकी वित्तीय जिम्मेदारियाँ सबसे अधिक होती हैं.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के वितरण प्रमुख (चीफ ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन), श्री भरत गुंटी ने कहा, 'वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी ग्राहकों की उम्मीदें उनके जीवन के लक्ष्यों के साथ

लगातार बदलती रहती हैं.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ग्राहकों को उनकी वित्तीय यात्रा के अलग-अलग चरणों में अत्यावश्यक पहलुओं को सुरक्षित रखने में मदद करती है. आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस हमारे सुरक्षा पोर्टफोलियो में 10 साल की पॉलिसी अवधि जोड़कर ग्राहकों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण को रेखांकित करता है. इसमें किफायत के साथ-साथ ऐसे फीचर शामिल हैं जो सही मायने में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं. 'आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस के ज़रिए, ग्राहकों को जानलेवा बीमारी का पता चलने पर100% बीमा राशि (सम अश्योर्ड) मिलती है.

इस प्लान में विशेष रूप से सुनिश्चित प्रीमियम के साथ 'क्रिटिकल इलनेस' (गंभीर बीमारी) सुरक्षा का विकल्प है, जो हर साल नहीं बढ़ता है. इस प्लान में 67,100 रुपए तक की नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेवा भी शामिल हैं और ग्राहकों को 3 लाख रुपए तक का तुरंत दावा भुगतान भी मिलता है.

> गौरतलब है कि कंपनी का दावा निपटान अनुपात 99.3% रहा, जो उद्योग में अग्रणी है. साथ ही, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के दौरान एक दिन की औसत दावा निपटान अवधि के साथ, हम ग्राहकों और उनके परिवारों की मदद के लिए उस वक्त हमेशा उपस्थित रहते हैं, जब उन्हें हमारी सबसे अधिक ज़रूरत होती है.कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के दौरान, 1,306 करोड़ रुपए के मृत्यु से जुड़े दावे का निपटान किया और परिपक्वता तथा उत्तरजीविता (सर्वाइवल) लाभ के तौर पर 3,360 करोड़ रुपए का भुगतान किया. इससे पॉलिसीधारकों को समय पर वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करने के प्रति आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की प्रतिबद्धता रेखांकित होती है.

जुलाई में भारत का निर्यात 19 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली, 13 अगस्त वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के निर्यात क्षेत्र ने जुलाई में मजबूत प्रदर्शन किया है. देश का निर्यात जुलाई 2026 में 19.63 प्रतिशत बढ़कर 44.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया. हालांकि इसी अवधि में आयात में भी तेजी रही, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 31.98 अरब डॉलर हो गया.

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में आयात करीब 17.52 प्रतिशत बढ़कर 76.22 अरब डॉलर दर्ज किया गया. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत का निर्यात 17.04 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 173.78 अरब डॉलर पहुंच गया. वहीं इस अवधि में आयात 19.27 प्रतिशत बढ़कर 292.38 अरब डॉलर रहा. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि जुलाई में भारत के निर्यात में बढ़ोतरी के पीछे पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों की मजबूत मांग प्रमुख कारण रही.

वाहनों की थोक बिक्री ने बनाया जुलाई का रिकॉर्ड

नयी दिल्ली, 13 अगस्त वाहनों की बिक्री में पिछले साल सितंबर में शुरू हुई तेजी अब तक जारी है और थोक बिक्री के मामले में जुलाई महीने का नया रिकॉर्ड बना है.

वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री 34.3 प्रतिशत के जबरदस्त उछाल के साथ 4,57,810 इकाई पर पहुंच गयी. इसमें कार, उपयोगी वाहन और वैन शामिल हैं. दुपहिया वाहनों की बिक्री 22.6 प्रतिशत बढ़ी और 19,23,484 इकाई दर्ज की गयी. इसमें मोटरसाइकिलों की बिक्री 10,74,796 इकाई और स्कूटरों की 7,98,190 इकाई रही. सालाना आधार पर इनमें क्रमश: 20.7 प्रतिशत और 23.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ. जुलाई में कुल 50,497 मोपेड बिके.

महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को नया सहारा

भोपाल, 13 अगस्त आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट हर लॉन्च किया है. यह खासतौर पर महिलाओं के लिए तैयार किया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म प्लान है.

इस प्लान को लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ और वेलनेस फायदों को जोड़कर महिलाओं की बदलती सुरक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट हर महिलाओं के जीवन के अहम् पड़ावों पर उन्हें मज़बूत और सुरक्षित बनाने के लिए कई खास सुविधाएँ प्रदान करता है. इसमें 15% लाइफटाइम प्रीमियम डिस्काउंट, महिला-विशेष हेल्थ मैनेजमेंट और वेलनेस सेवाएँ और प्रेग्नेंसी ब्रेक फीचर जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जिससे महिलाएँ प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी प्रीमियम किश्तों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं. इसके अलावा, यह प्लान चाइल्ड एजुकेशन केयर भी प्रदान करता है, जिसमें 10 साल तक हर साल बढ़कर मिलने वाली इनकम का लाभ मिलता है.

इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को मिलने वाला डेथ बेनिफिट अगले 10 सालों तक हर साल 10% बढ़कर नियमित आय के रूप में मिलता है.इस लॉन्च के बारे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, श्री विकास गुप्ता ने कहा, 'भारतीय महिलाएँ कई भूमिकाएँ निभाती हैं. इस वजह से उनकी वित्तीय योजना की जरूरतें अलग होती हैं और जीवन के अलग-अलग चरणों में बदलती रहती हैं. आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट हर को व्यापक सुरक्षा देने के साथ ही उनकी अनोखी स्वास्थ्य और वेलनेस जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

> आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, जो ग्राहकों का भविष्य सुरक्षित करें और उन्हें मज़बूत बनाएँ. ग्राहकों को सबसे आगे रखने की यह सोच कंपनी के वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजों में भी साफ दिखती है, जहाँ क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.3% के साथ इंडस्ट्री में सबसे आगे है और नॉन-इन्वेस्टिगेटिव इंडिविजुअल डेथ क्लेम का औसत सेटलमेंट टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) सिर्फ 1 दिन है.

समाचार विशेष

सीएम विजय ने बदल दी राजनीति!

केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ

चेन्नई. तमिलनाडु की सी जोसेफ विजय सरकार ने दो दिनों के भीतर मोदी सरकार के दो प्रमुख प्लान परिसीमन और एफसीआरए के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित किए हैं. सीएम विजय ने खुद विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव लाए. इससे पहले मंगलवार को एफसीआरए बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया.

दिलचस्प है कि इस प्रस्ताव का कट्टर विरोधी एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने समर्थन किया. परिसीमन और एफसीआरए के खिलाफ ऐसा कदम उठाने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है. परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव में अपील की गई है कि केंद्र लोकसभा सदस्यों की संख्या को 543 निर्धारित रखे. इसपर विधानसभा में करीब 2 घंटे तक तीखी बहस चली. इसके बाद सदन से मंजूरी मिल गई.

क्या बोले उदयनिधि स्टालिन?- डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमारा रुख है कि अगले 25 वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन नहीं किया जाना चाहिए. हम महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण पर प्रस्ताव का स्वागत करते हैं. जिस आंदोलन ने सबसे पहले भारत को बताया कि परिसीमन का प्रभाव क्या होगा, वह डीएमके है. इसके बाद टीवीके ने डीएमके को थैंक्यू कहा. विधानसभा में तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए ष्ठस्ख्य का धन्यवाद करते हैं, भले ही हमारे राजनीतिक मतभेद हों. डीएमके का यह कदम काफी महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि अभी तक ऐसी खबर आ रही थी कि डीएमके परिसीमन बिल पर सरकार का समर्थन कर सकती है, लेकिन अब विधानसभा में डीएमके ने अलग स्टैंड लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा, परिसीमन की वजह से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए.

> **एफसीआरए पर प्रस्ताव**
>
> इससे पहले मंगलवार को विजय सरकार विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ प्रस्ताव लायी. इसका भी डीएमके ने समर्थन किया. स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन से परमार्थ संगठनों की स्वायत्तता विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के माध्यम से चलाए जा रहे शैक्षणिक और समाज कल्याण संस्थानों के कामकाज पर असर पड़ सकता है. मोदी सरकार मौजूदा मानसून सत्र में एफसीआरए बिल को पास कराने की प्लानिंग में थी, लेकिन विपक्षी दलों और ईसाई संगठनों के विरोध के बीच इस फैसले को टाल दिया है.

खरगे की रैली के बाद कुमाऊं की सियासत गरमाई

वायरल वीडियो और कथित नारों पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

नैनीताल. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आठ अगस्त को हल्द्वानी में हुई विजय शंखनाद रैली के बाद कुमाऊं की सियासत अचानक गरमा गई है.

रैली के मंच से लेकर उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कथित नारों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अब सड़क से लेकर कोतवाली तक पहुंच चुके हैं. दोनों दल इस पूरे घटनाक्रम को आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार करने के नजरिये से देख रहे हैं.

भाजपा ने रैली के दौरान रामलीला मैदान में अल्लाह हो अकबर जैसे नारे लगाए जाने का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया.

> **दोनों दल आक्रामक**
>
> इस पूरे विवाद के पीछे केवल रैली में लगाए गए कथित नारों का मुद्दा नहीं, बल्कि कुमाऊं में बदलते राजनीतिक समीकरण भी दिखाई दे रहे हैं. रैली से पहले जहां कांग्रेस और भाजपा की गतिविधियां अपेक्षाकृत धीमी थीं, वहीं खरगे के कार्यक्रम के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां इस विवाद के जरिये अपने-अपने समर्थक वर्ग को लामबंद करने और चुनावी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही हैं.

विजय, ममता जैसा बनना है पीके को

पटना. बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का ग्राफ अचानक बहुत ऊंचा हो गया है. इसका कारण एक तो बांकीपुर सीट में ही छिपा है. यह सीट मिनी बिहार की तरह है. कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा, जहां के लोग बांकीपुर में नहीं रहते हैं. ज्यादातर लोग सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करने वाले लोग उस क्षेत्र में रहते हैं.

दूसरा कारण यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और तीसरा कारण यह है कि भाजपा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना कर चुनाव लड़ा था. इस सीट पर जीत से यह भी प्रमाणित हुआ है कि लगातार जमीन पर मेहनत करके जीत हासिल हो सकती है. प्रशांत किशोर की जिद, जुनून और रणनीति सबकी कामयाबी है. माना जा रहा है कि किसी समय वे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. तभी एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वे बिहार के अरविंद केजरीवाल हैं?

इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने जो कहा वह बहुत दिलचस्प है. उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि वे विजय और ममता बनर्जी क्यों नहीं हैं? ध्यान रहे प्रशांत किशोर ने केजरीवाल, विजय और ममता बनर्जी तीनों के चुनाव में रणनीतिक प्रबंधन का काम किया है. लेकिन वे अपने को विजय या ममता बनर्जी जैसा बनाना चाहते हैं. वे केजरीवाल नहीं बनना चाहते हैं इसका क्या कारण हो सकता है? यह तो पक्के तौर पर प्रशांत किशोर ही बता सकते हैं. हो सकता है कि वे केजरीवाल की राजनीतिक स्टाइल को पसंद नहीं करते हों. लेकिन यह तय है कि वे बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. ध्यान रहे चाहे केजरीवाल हों या विजय या ममता बनर्जी, तीनों मुख्यमंत्री बने.

विशेष | **अमेठी में विपक्षी नेताओं के साथ भाजपा नेता भी बेचैन**

स्मृति की सक्रियता से भाजपा दावेदार परेशान?

अमेठी. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की अमेठी को लेकर बढ़ी सक्रियता ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है. कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, चित्रकूट धाम तक ट्रेन की सौगात की घोषणा और अमेठी से बहन वाले रिश्ते का जिक्र, इन तमाम सियासी घटनाक्रमों ने अमेठी के गलियारों में चर्चा का बाजार फिर से गर्म कर दिया है. विरोधी दलों के साथ-साथ इस सक्रियता से भाजपा के भीतर टिकट व पद की चाहत रखने वाले नेताओं और जुबानी जंग लड़ने वाले बयानवीरों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं.

आम चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अमेठी में कांग्रेस की वापसी शायद ही निकट भविष्य में संभव हो सके. लेकिन, साल 2023 के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति बदलते हुए जायस नगर पालिका परिषद की सीट पर विशेष फोकस किया और भाजपा तथा सपा के उम्मीदवारों को पछाड़कर शानदार जीत दर्ज की. यहीं से कांग्रेस के रणनीतिकारों को एक बार फिर अमेठी को अपने पाले में खींचने की उम्मीद नजर आई.

इसका असर आम चुनाव 2024 में साफ दिखाई दिया, जब कांग्रेस ने सोची-समझी रणनीति के तहत केएल शर्मा को मैदान में उतारा और पूरी पार्टी उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हो गई. समाजवादी पार्टी का साथ मिलने से हाथ को और मजबूती मिली और वे स्मृति इरानी के मुकाबले चुनावी दंगल जीतने में सफल रहे. दूसरी ओर, जमीनी हकीकत यह रही कि भाजपा के भीतर ही कुछ नेताओं ने स्मृति के पक्ष में हवा का दावा तो खूब किया, लेकिन धरातल पर वह मेहनत नदारद रही जो वोट में तब्दील होती है.

> **स्मृति इरानी ने चलाया था लोगों को जोड़ने का सिलसिला**
>
>
>
> गौरतलब है कि 2014 से लेकर 2024 तक स्मृति इरानी ने अमेठी के गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को भाजपा परिवार से जोड़ने का जो सिलसिला चलाया था, उसका असर आज भी कायम है. आम चुनाव हारने के बावजूद आज भी उनके समर्थकों और शुभचिंतकों का दायरा अन्य नेताओं के मुकाबले काफी बड़ा है. इसी भावनात्मक जुड़ाव और जनाधार को भाजपा 2027 के चुनावी समर में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में जुटी है. खास बात यह है कि जिले के सांगठनिक ढांचे पर स्मृति की मजबूत पकड़ पहले की तरह आज भी बरकरार है.